

प्रेषक,
पी०के० महान्ति
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक/ 8 दिसम्बर, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4524-25/लेखा बजट/2007-08 दिनांक 29.11.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या 740/XIV-1/2007 दिनांक 22.8.2007 के क्रम में निम्नलिखित अवचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रु० 766 हजार (रुपये सात लाख छियासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या- 18

2425-सहकारिता आयोजनेत्तर

001-निदेशन तथा प्रशासन

05- सहकारी न्यायाधिकरण

02-मजदूरी

04-यात्रा व्यय

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय

07-मानदेय

08-कार्यालय व्यय

16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व

18-प्रकाशन

22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता

27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति

29-अनुरक्षण

42-अन्य व्यय

44- प्रशिक्षण

45-अवकाश यात्रा व्यय

योग:-

धनराशि

(हजार रुपये में)

20.00

15.00

20.00

5.00

25.00

100.00

384.00

10.00

12.00

100.00

5.00

10.00

10.00

50.00

766.00

(रुपये सात लाख छियासठ हजार मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हरतपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी०एम० 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-सहकारी न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अरम्भोपत्र संख्या-210(NP)/XXVII-4/ दिनांक 12.12.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी०के० महान्ति)
सचिव।

संख्या 1146/XIV-1/ 2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फ़ाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।